

पंचायत उन्नत सूचकांक

प्रलिस के लयः

पंचायत उन्नत सूचकांक (PAI), [राष्ट्रीय पंचायती राज दविस](#), [राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा](#), [73वाँ संवधान संशोधन अधनियम](#), [भौगोलिक सूचना प्रणाली](#)

मेन्स के लयः

[PRI का वततीय सशक्तीकरण](#), पंचायती राज संस्थाओं से संबंधति मुद्दे, सतत् विकास लक्ष्य

[स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने [राष्ट्रीय पंचायती राज दविस \(24 अपरैल\)](#) पर पंचायत उन्नत सूचकांक (PAI) को स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और [सतत् विकास लक्ष्यों \(SDG\)](#) से संबद्ध वषियों पर 2.16 लाख पंचायतों की रैकगि करके वकिसति भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया ।

पंचायत उन्नत सूचकांक क्या है?

- **परचिय:** PAI एक समग्र सूचकांक है जसि सामाजकि-आर्थकि संकेतकों का उपयोग कर समग्र भारत केग्राम पंचायतों (GP) के प्रदर्शन और प्रगतिका आकलन करने हेतु अभकिल्पति कथिा गया है । इसमें वकिस अभाव की पहचान की जाती है और साक्ष्य-आधारति नयोजन में सहायता मलित्ती है ।
 - यह [सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) द्वारा वकिसति [सतत् विकास लक्ष्यों \(LSDG\) के स्थानीयकरण](#) और [राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवरक \(NIF\)](#) के अनुरूप है ।
 - यह भागीदारीपूर्ण, ऊर्ध्वगामी शासन को बढ़ावा देने, सामाजकि-आर्थकि संकेतकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के वकिस का आकलन करने, सुधार क्षेत्रों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारति नयोजन को सक्षम बनाने के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

पंचायत उन्नति सूचकांक का उद्देश्य

विशेषता	उद्देश्य
प्रगति का मापन	LSDG पर वृद्धिशील प्रगति का मापन
पंचायतों का वर्गीकरण	LSDG प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण
विकास प्राथमिकता	साक्ष्य आधारित मूल्यांकन और नियोजन
विकासात्मक प्रगति	प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिये बेहतर विधि
तुलना	कोई अंतर-राज्यीय तुलना नहीं, लेकिन राज्य के भीतर तुलना संभव है



Made with  Napkin

- **PAI के संकेतक:** यह 9 LSDG-संरक्षित वर्षों पर 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों पर आधारित है।
 - इसे पंचायत स्तर के विकास का मल्टी-डोमेन और बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकन प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

Indicator Framework used for PAI Score Calculation 2022-23



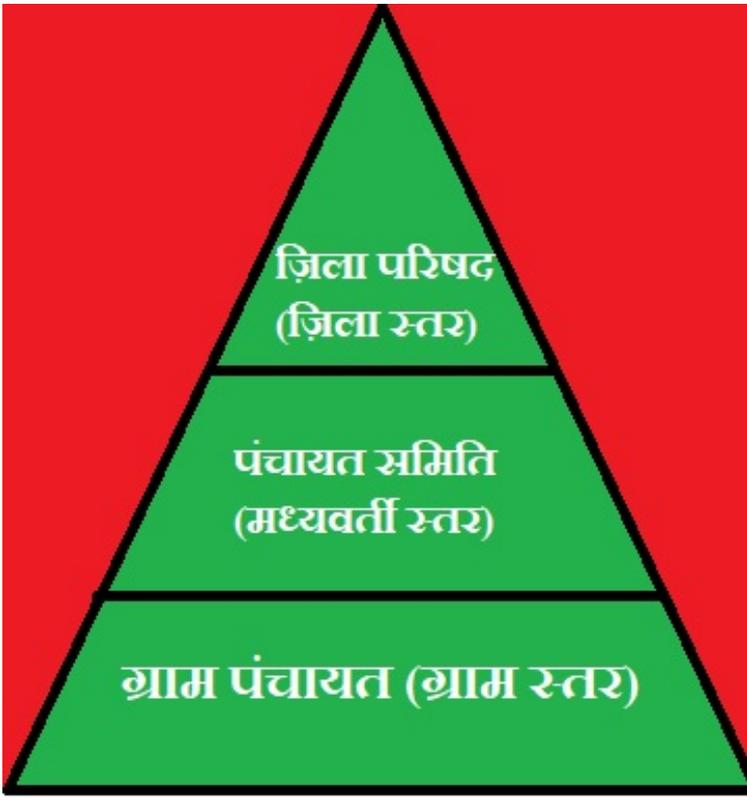
Theme	Indicator Count	Total Data Points
Theme 1 - Poverty Free and Enhanced Livelihoods Panchayat	32	60
Theme 2 - Healthy Panchayat	21	42
Theme 3 - Child Friendly Panchayat	82	143
Theme 4 - Water Sufficient Panchayat	21	34
Theme 5 - Clean and Green Panchayat	33	58
Theme 6 - Self-sufficient Infrastructure in Panchayat	159	189
Theme 7 - Socially Just and Socially Secured Panchayat	62	100
Theme 8 - Panchayat with Good Governance	62	87
Theme 9 - Women Friendly Panchayat	44	81
Total	516	794

Unique Indicator	Mandatory Indicator	Optional Indicator	Unique Data Points	Numeric Indicators	Binary Indicators
435	331	104	566	207	228

- **डेटा संग्रह और सत्यापन:** 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने PAI पोर्टल पर डेटा दर्ज किया है। डेटा प्रविष्टियों को शामिल करने से पहले संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- **GP की प्रदर्शन श्रेणियाँ:** PAI और वषियगत स्कोर के आधार पर, GP को पाँच प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: **अचीवर (90+)**, **फ्रंट रनर (75-89.99)**, **परफॉर्मर (60-74.99)**, **एस्पिरेंट (40-59.99)** और **बगिनर (40 से नमिन)**।
- **वर्ष 2022-23 का PAI डेटा:** 2.56 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.16 लाख ने मान्य डेटा प्रस्तुत किया। कोई भी पंचायत अचीवर के रूप में योग्य नहीं पाई गई, जबकि 0.3% को फ्रंट रनर, 35.8% को परफॉर्मर, 61.2% को एस्पिरेंट्स और 2.7% को बगिनर के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992:** इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों में चुनाव, आरक्षण और शक्तियों के हस्तांतरण के प्रावधानों के साथ **त्रिसंघीय प्रणाली** का निर्माण किया।
 - **संवैधानिक भाग IX** को 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया तथा जिसका शीर्षक **"पंचायत"** है, इसमें **अनुच्छेद 243 से 243-O** तक शामिल हैं तथा इसमें पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, संयोजन, निर्वाचन, शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख किया गया है।
 - इसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई **11वीं अनुसूची** में पंचायतों को नरिदष्टित किये गए 29 वषियों की सूची दी गई है, जिसमें प्रभावी स्थानीय शासन के लिये उनकी शक्तियाँ, प्राधिकार और ज़म्मेदारियों का विवरण दिया गया है।
- **अनुच्छेद 40 (राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत):** यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें उचित रूप से सशक्त बनाने का नरिदेश देता है।



पंचायतों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमिति वित्तीय स्वायत्तता:** पंचायतें राज्य और केंद्रीय नधियों पर बहुत अधिक नरिभर हैं। [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) के एक अध्ययन (वर्ष 2022-23) के अनुसार, प्रति पंचायत औसत राजस्व 21.23 लाख रुपए था, लेकिन केवल 1.1% ही उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों (स्थानीय कर, शुल्क) से आया।
 - 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26) ने नोट किया कि केवल 8 राज्यों ने अपने छटे राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन किया है, जबकि इसकी नयित तर्था वरष 2019-20 है। इससे पंचायतों के वकिस और सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
 - इसके अतरिकित, स्थानीय कर संग्रहण ग्राम पंचायतों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से शक्तीहीन बना हुआ है।
- **अपूर्ण हस्तांतरण:** 73वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को 29 वषियों का हस्तांतरण अनवार्य किया गया है, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय की वरष 2022 की रपिर्ट से पता चला है कि 20% से भी कम राज्यों ने इस हस्तांतरण को पूरी तरह से लागू किया है।
- **तकनीकी और क्षमता अंतराल:** डजिटल बुनयादी ढाँचे और साकषरता की कमी नगिरानी, मूल्यांकन और डेटा रपिर्टगि में बाधा डालती है।
 - 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पंचायतें कंप्यूटर से सुसज्जित हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक भी नहीं है, तथा ओडिशा में केवल 13% ही कंप्यूटर से सुसज्जित हैं। इंटरनेट की पहुँच भी नमिन है, हरयाणा और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः 0% और 1% कनेक्टिविटी की रपिर्ट है।
 - कई पंचायतों में वकिस योजनाओं की डजिइनगि, नगिरानी और मूल्यांकन के लयिप्रशक्षित करमचारयिों और तकनीकी सलाहकारों का अभाव है।
- **अपर्याप्त बुनयादी ढाँचा:** केवल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पक्के (स्थायी) पंचायत कार्यालय भवन हैं।
 - अरुणाचल प्रदेश में यह दर सबसे कम है, जहाँ केवल 5% पंचायत कार्यालय पक्के भवनों में स्थित हैं।
- **प्रतनिधित्व में अंतराल:** पंचायतों में महिलाओं के लयि 50% कोटा होने के बावजूद, मध्य प्रदेश, हरयाणा, पंजाब और त्रपुरा जैसे राज्य पीछे रह गए हैं।
 - नरिवाचति प्रतनिधियिों में महिलाओं की हसिसेदारी 46.6% है, लेकिन "प्रधान पति" मुद्दे के कारण उनकी भागीदारी सीमित है, जहाँ पुरुष रशितेदार प्रायः नरिणय लेने की प्रकरया को नर्यितरति करते हैं।
 - पत्तिसत्तात्मक मानदंड और नौकरशाही की उपेक्षा ने कई राज्यों, वषिषकर उत्तर प्रदेश, बहिर, हरयाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी कषेत्रों में महिलाओं को नाममात्र का मुखया बना दिया है।
- **अंतर-वभागीय समनवय में कमी:** एक ही गाँव में कई सरकारी वभाग अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अभसिरण की कमी से कार्यों का दोहराव होता है और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की प्रभावशीलता और स्वायत्तता को बढ़ाने के लयि कौन से उपाय कयि जा सकते हैं?

- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और कनि स्रोतों की खोज कर सकती हैं? (मुख्य परीक्षा, 2018)

प्रश्न. आपकी राय में भारत में शक्त के वकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन-परदृश्य को कसि सीमा तक परिवर्तित किया है? (मुख्य परीक्षा, 2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/panchayat-advancement-index>

